पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1956 का विविध न्यायिक मामला सं. 939

इस पर निर्णय लेता हैः 08.04.1963

याचिकाकर्तागणः **ब्रज किशोर बहादुर**

बनाम

उत्तरदाताः बिहार राज्य और अन्य

विचाराधीन मुद्दाःआरा के अनुमंडल अधिकारी के आदेश पर बुलाने के संबंध में याचिका–बिहार निजी सिंचाई कार्य अधिनियम की धारा 5ए के तहत कार्यवाही शुरू करना–आरा के अतिरिक्त अनुमंडल अधिकारी का आदेश, याचिकाकर्ता को शाहाबाद जिले के गाँव बाबूबंध, तौज़ी संख्या 3695 में आहार की मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए कहना बिहार निजी सिंचाई कार्य अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के तहत–संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करके रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

क्या वर्तमान मामले में आरा के अनुमंडल अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5ए की अपेक्षाओं मापदंड का पालन किया गया है और याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अनुमंडल अधिकारी का आदेश अवैध है और बिना क्षेत्राधिकार के है अधिनियम की धारा 5ए की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है।

अभिनिर्धारणः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान मामले में अनुमंडल अधिकारी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण दिए हैं कि धारा 3 के तहत नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के कारण मौजूदा सिंचाई कार्य की मरम्मत में देरी से उन भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जो पानी की आपूर्ति के लिए ऐसे सिंचाई कार्य पर निर्भर थी। यह देखा गया है कि अनुमंडल अधिकारी ने 18 मई, 1949 के अपने आदेश में उल्लेख किया है कि "इस तथ्य से एक आपातकाल पैदा हो गया है कि भोजन की भारी कमी थी", कि "उनके पास बहुत सीमित

समय बचा है", कि "गाँव में आहार की मरम्मत की बहुत खराब स्थिति थी" और "जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई सुविधाएं खराब हो गई हैं और उपज सही नहीं है"।इन सभी कारणों से आरा के अनुमंडल अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि अधिनियम की धारा 3 के तहत नियमित सूचना द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है, तो देरी से उन भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पानी की आपूर्ति के लिए इस तरह के सिंचाई कार्य पर निर्भर हैं।यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में आरा के अनुमंडल अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए की आवश्यकता का पालन किया गया है और याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अनुमंडल अधिकारी का आदेश अवैध है और अधिनियम की धारा 5 ए की मापदंड अपेक्षाओं का पालन न करने के लिए अधिकार क्षेत्र के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि आरा के अनुमंडल अधिकारी के सामने उनके इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि भोजन की भारी कमी थी

अभिनिर्धारणः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सामग्री की अनुपस्थिति का प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और कार्यवाही के वर्तमान चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में अधिनियम की धारा 5 ए के तहत अनुमंडल अधिकारी द्वारा अपने आदेश में दिए गए कारणों की पर्याप्तता को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामले में याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना निश्चित रूप से खुला है कि अनुमंडल अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर अधिनियम की धारा 5 ए के तहत आदेश आधारित हो, हालांकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई बिंदु उठाया नहीं गया था जब अपील शाहाबाद के कलेक्टर के समक्ष दायर की गई थी और पटना डिवीजन के आयुक्त के समक्ष दायर पुनरीक्षण आवेदन में भी।याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर कोई हलफनामा भी दायर नहीं किया गया था।

पटना के उच्च न्यायालय में

पूर्ण पीठ

1956 का विविध न्यायिक मामला सं. 939

इस पर निर्णय लेता हैः 08.04.1963

याचिकाकर्तागणः **ब्रज किशोर बहादुर**

बनाम

उत्तरदाताः **बिहार राज्य और अन्य**

माननीय न्यायाधीश/कोरमः

वैद्यनाथिर रामास्वामी, मुख्य न्यायमूर्ति , कमला सहाय और कन्हैया सिंह, न्यायमूर्ति

सलाहकारः

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/वादी के लिएः जगत नारायण प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए: अतिरिक्त सरकार प्लीडर

आदेश

1. इस मामले में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय नियम प्राप्त किया है, जिसमें प्रतिवादियों को यह कारण दिखाने के लिए कहा गया है कि आरा के उप–मंडल अधिकारी का आदेश, दिनांक 18 मई, 1959, बिहार निजी सिंचाई कार्य अधिनियम की धारा 5ए के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए, और आरा के अतिरिक्त उप–मंडल अधिकारी का आदेश, दिनांक 25 अक्टूबर, 1954, जिसमें याचिकाकर्ता को शाहाबाद जिले के गाँव बाबूबंध, तौज़ी संख्या 3695 में आहर की मरम्मत की लागत 1145/8 रु. तक को पूरा करने के लिए कहा गया है। बिहार निजी सिंचाई कार्य अधिनियम, 1922 के प्रावधानों के तहत, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के अनुदान द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

2. कारण, उन उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान अतिरिक्त सरकारी प्लीडर द्वारा दिखाया गया है जिन्हें नियम की सूचना देने का आदेश दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बिहार निजी सिंचाई कार्य अधिनियम की धारा 5ए के तहत आरा के विद्वान उप–मंडल अधिकारी का 18 मई, 1949 का आदेश अधिकारातीत और अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि उस धारा की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मरम्मत कार्य की लागत की प्राप्ति के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई बाद की कार्यवाही भी अधिकार क्षेत्र से बाहर और अधिकारेत्तर है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि 18 मई, 1949 का अफरा के उप–मंडल अधिकारी का आदेश अधिकारेत्तर है क्योंकि उन्होंने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कारण नहीं दिए हैं कि मौजूदा सिंचाई कार्य की मरम्मत में देरी, जो धारा 3 के तहत एक नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के कारण हो सकती है, धारा 5ए की उप–धारा (i) के उत्तरार्ध में निर्धारित परिणामों का कारण बनेगी या होने की संभावना है।

इस तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने मोंघिर के कलेक्टर बनाम केशव प्रसाद मनु/एससी/0008/1962 मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले पर भरोसा कियाःए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1694 जिसमें धारा 5ए की व्याख्या का प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। हमारी राय में वर्तमान मामला मनु/एस. सी./0008/1962 ए.आाई. अर 1962 एस.सी 1964 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भीतर नहीं आता हैः क्योंकि धारा 5ए के तहत उप–मंडल अधिकारी के आदेश की शर्तें, जो उस मामले में विचार का विषय थी, 18 मई, 1949 के आरा के उप–मंडल अधिकारी के आदेश की शर्तों से स्पष्ट रूप से अलग हैं, जिसकी वैधता को वर्तमान मामले में हमारे सामने चुनौती दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के मामले में धारा 5ए के तहत उप–मंडल अधिकारी का आदेश इस प्रकार हैः

> "जबकि मुझे ऐसा लगता है कि गाँव में स्थित मौजूदा सिंचाई कार्य की मरम्मत. थाना. जिला मोंघिर उपरोक्त गाँव के लाभ के लिए आवश्यक है और इस तरह के सिंचाई कार्य की मरम्मत की विफलता प्रतिकूल रूप ग्राम प्रभावित होती है और उन भूमि को प्रतिकूल रूप ग्राम प्रभावित करने की संभावना है जो पानी की आपूर्ति के लिए उस पर निर्भर हैं, और

> "जबकि मैं संतुष्ट हूं कि मेरा हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि, मेरी राय में, मौजूदा सिंचाई कार्य की मरम्मत में देरी, जो धारा 3 के तहत एक नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के कारण हो सकती है, उस भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है जो पानी की आपूर्ति के लिए इस तरह के सिंचाई कार्य पर निर्भर करती है, बी. पी. आई. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 5ए के तहत आगे बढ़ना समीचीन माना जाता है। इसलिए मैं एतद्द्वारा आदेश देता हूं कि उक्त कार्य को उक्त अधिनियम की धारा 5ए के तहत तुरंत निष्पादित किया जाए। धारा 5ए के तहत उपरोक्त ग्राम में एक सुविधाजनक स्थान पर एक सार्वजनिक सूचना दी जानी चाहिए कि उसमें उल्लिखित कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। "

उप–विभागीय अधिकारी, आरा, दिनांक 18 मई, 1949 का आदेश, जिसके साथ हम इस मामले में संबंधित हैं, इस प्रकार हैः

> "एक आपात स्थिति इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि भोजन की भारी कमी है और इसे सुधारने के लिए आहार की मरम्मत आवश्यक हो गई है। हमारे पास बचा समय बहुत सीमित है और यदि पी. आई. अधिनियम 1923 की धारा 3 के तहत एक नोटिस द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है तो मरम्मत में देरी होगी। देरी से उन भूमि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पानी की आपूर्ति के लिए इस तरह के सिंचाई कार्य पर निर्भर हैं। मुझे संतोष है कि ग्राम में आहर की मरम्मत की बहुत खराब स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप सिंचाई की सुविधाएँ खराब हो गई हैं और उपज सही नहीं है।
>
> इसलिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अहर की मरम्मत की जाए और इसे तुरंत पूरा किया जाए।
>
> इसलिए, मैं पी. आई. अधिनियम 1922 की धारा 5ए के तहत धारा में परिकल्पित नोटिस जारी करने का आदेश देता हूं। "

यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में उप–मंडल अधिकारी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण दिए हैं कि धारा 3 के तहत नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के कारण मौजूदा सिंचाई कार्य की मरम्मत में देरी से उन भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जो पानी की आपूर्ति के लिए ऐसे सिंचाई कार्य पर निर्भर थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उप–मंडल

अधिकारी ने 18 मई, 1949 के अपने आदेश में कहा है कि "इस तथ्य ग्राम एक आपातकाल पैदा हो गया है कि भोजन की भारी कमी थी", कि "उनके पास बहुत सीमित समय बचा है", कि "गाँव में आहार की मरम्मत की स्थिति बहुत खराब थी" और "जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई सुविधाएं बदतर हो गई हैं और प्रस्तुत सही नहीं है"। इन सभी कारणों से आरा के उप–मंडल अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि अधिनियम की धारा 3 के तहत नियमित सूचना द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है, तो देरी से उन भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पानी की आपूर्ति के लिए इस तरह के सिंचाई कार्य पर निर्भर हैं। हमारी राय में वर्तमान मामले में आरा के उप–मंडल अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए की आवश्यकता का पालन किया गया है और हम याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उप–मंडल अधिकारी का आदेश अवैध है और अधिनियम की धारा 5 ए की आवश्यकता का पालन न करने के लिए अधिकार क्षेत्र के बिना है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आरा के उप–मंडल अधिकारी के सामने उनके इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि भोजन की भारी कमी थी। हम इस तर्क को सही के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में याचिकाकर्ता के लिए अधिनियम की धारा 5 ए के तहत अपने आदेश में उप–मंडल अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों की पर्याप्तता को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामले में याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना निश्चित रूप से खुला है कि उप–मंडल अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर अधिनियम की धारा 5 ए के तहत आदेश आधारित हो, हालांकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई बिंदु नहीं लिया गया था जब अपील शाहाबाद के आयुक्त समक्ष दायर की गई थी और पटना डिवीजन के आयुक्त के समक्ष दायर पुनरीक्षण आवेदन में भी। याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर इस मुद्दे पर कोई हलफनामा भी नहीं था। यह स्पष्ट है कि सामग्री की अनुपस्थिति का प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और कार्यवाही के इस चरण में इस प्रश्न में जाना हमारे लिए खुला नहीं है।

5. हमने जो कारण दिए हैं, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। हम तदनुसार आवेदन को खारिज करते हैं। अर्थ दंड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।